पाकिस्तान के राष्ट्रपति जरदारी अस्वस्थ कराची के अस्पताल में भर्ती कराया गया

इस्लामाबाद

पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को कराची के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल में उनके स्वास्थ्य की जांच की गई है। उन्हें जल्द ही अस्पताल से छुट्टी मिलने की उम्मीद है। मीडिया में उनके अस्पताल में भर्ती होने की खबरें आने के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मंगलवार को राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी से संपर्क किया और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली।

हालांकि राष्ट्रपति कार्यालय या पीपीपी की ओर से अपने सह अध्यक्ष के स्वास्थ्य के बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। सुबह मीडिया आउटलेट्स ने सूत्रों के हवाले से बताया कि राष्ट्रपति जरदारी को नवाबशाह से लाए जाने के बाद कराची के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पार्टी के एक करीबी सूत्र ने बताया कि उनकी कुछ जांचें की जा रही हैं और उन्हें जल्द ही छुट्टी दे दी जाएगी।

प्रेस सूचना विभाग की ओर से जारी बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री शहबाज ने राष्ट्रपति से संपर्क किया और उनका हालचाल पूछा और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।

इस बीच, सिंध के गवर्नर कामरान टेसोरी के कार्यालय ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति के चिकित्सक डॉ. असीम हुसैन को फोन कर जरदारी के स्वास्थ्य के बारे में पूछा और अपनी शुभकामनाएं व्यक्त कीं। अक्टूबर 2024 में विमान से उतरते समय राष्ट्रपति के पैर में फ्रैक्चर हो गया था। गिरने के बाद उन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। जांच के बाद डॉक्टर ने उनके पैर में प्लास्टर चढ़ा दिया।

69 वर्षीय राष्ट्रपति को हाल के वर्षों में स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं हुई हैं। मार्च 2023 में उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात में आंख की सर्जरी करवाई।

न्यूज ब्रीफ

बांग्लादेश में ढाका-चटगांव राजमार्ग पर 12 घंटे में दो हादसे, 10 की मौत, 27 घायल

ढाका। बांग्लादेश के ढाका-चटगांव राजमार्ग पर लगभग 12 घंटों के दौरान दो सड़क हादसे में 10 यात्रियों की मौत हो गई और 27 लोग घायल हो गए। सुबह हुए हादसे में जान गंवाने वाले सात लोगों में से किसी की भी अब तक पहचान नहीं हो पाई है। सुबह करीब सात बजे चटगांव के लोहागरा उप जिला में ढाका-चटगांव राजमार्ग पर एक यात्री बस और एक मिनी बस के बीच हुई आमने-सामने की टक्कर में कम से कम सात लोगों की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए। लोहागरा पुलिस थाने के प्रभारी आरिफुर रहमान ने बताया कि मृतकों की पहचान नहीं हो सकी है। यह हादसा चुंटी राजमार्ग खंड के जंगलिया इलाके में हुआ। रिलैक्स परिवहन की बस की कॉक्स बाजार जा रही एक मिनी बस से टक्कर हो गई। मिनी बस के सात यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। सभी शव लोहागरा उप जिला स्वास्थ्य केंद्र भेज दिए गए हैं। इसके अलावा इसी राजमार्ग पर मंगलवार शाम करीब 6:30 बजे कुमिला के चंदिना उप जिला में एक बस के बिजली के खंभे और पेड़ से टकरा जाने से तीन यात्रियों (सभी पुरुष) की मौत हो गई और कम से कम 25 अन्य घायल हो गए। मृतकों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। घायलों को चंदिना उप जिला स्वास्थ्य केंद्र से कमिला मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया है।

नेपाल-थाईलैंड प्रधानमंत्रियों के बीच द्विपक्षीय वार्ता, कई समझौतों पर हुए हस्ताक्षर

काठमांडू। थाईलैंड की आधिकारिक यात्रा पर गए नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और थाईलैंड के प्रधानमंत्री पेटोंगट्रान शिनावात्रा के बीच बुधवार को बैंकाक में हुई मुलाकात में द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक मजबूत करने को लेकर चर्चा हुई। दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए हैं। बैंकाक में दोनों देशों के प्रधानमंत्री के बीच बैठक में शामिल हुई नेपाल की विदेश मंत्री डॉ. आरजू राणा देउवा ने कहा कि थाईलैंड के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापना के 65 साल के बाद पहली बार नेपाल के प्रधानमंत्री की आधिकारिक यात्रा होना अपने आप में ऐतिहासिक है। इससे पहले थाईलैंड की प्रधानमंत्री शिनावात्रा ने एक सरकारी इमारत में प्रधानमंत्री ओली का स्वागत किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच बैठक के बाद संस्कृति और पर्यटन क्षेत्रों में सहयोग से संबंधित एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गए। नेपाल की तरफ से विदेश मंत्री डॉ. आरजू ने समझौते पर हस्ताक्षर किए।

दक्षिण कोरियाः राष्ट्रपति के खिलाफ आए महाभियोग पर फैसला 5 को, 14 हजार सुरक्षाकर्मी तैनात

सोल। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल के खिलाफ आए महाभियोग पर फैसला 5 अप्रैल को होना है। कहीं कोई अप्रिय स्थिति न बने इसके लिए 14 हजार पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। राष्ट्रीय पुलिस एजेंसी ने पुलिस बलों को गैफो अलर्ट पर रखा है, जो उच्चतम स्तर है और सभी उपलब्ध पुलिस बलों को आपातकालीन स्टैंडबाय पर रखता है। सभी संवैधानिक न्यायालय के जजों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पुलिस संवैधानिक न्यायालय परिसर में घुसने का प्रयास करने वालों को तुरंत गिरफ्तार कर लेगी। यदि यून फैसले के लिए अदालत में उपस्थित होते हैं, तो पुलिस राष्ट्रपति निवास से संवैधानिक न्यायालय तक के मार्ग को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाएगी और रास्ते में उनके पक्ष या विपक्ष में प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों को अलग करेगी। लॉयर्स फॉर ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अध्यक्ष यून बोक-नाम, जिन्हें मिनब्यून के नाम से भी जाना जाता है, ने बताया कि यून के महाभियोग के फैसले की तारीख बहुत देर से आई है, लेकिन फिर भी यह राहत की बात है।हालांकि, संवैधानिक न्यायालय के पास यून समर्थक प्रदर्शनकारियों ने कोरियाई और अमेरिकी झंडे लहराते हुए महाभियोग खारिज करो के नारे लगाए। पुलिस ने कथित तौर पर न्यायालय की घोषणा के बाद मंगलवार दोपहर तक संवैधानिक न्यायालय के पास लगभग 3,200 कर्मियों को तैनात कर दिया। न्यायालय यदि महाभियोग प्रस्ताव को बरकरार रखता है, तो यून को पद से हटा दिया जाएगा। अगर इसे खारिज कर दिया जाता है, तो उन्हें मई 2027 तक अपने शेष कार्यकाल को पूरा करने के लिए बहाल कर दिया जाएगा।

इमरान के पुन : नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट होने पर घिरेगी सरकार

इस्लामाबाद

दुनियां में शानदार क्रिकेटर के तौर पर मशहूर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को दूसरी बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। उन्हें पाकिस्तान में मानवाधिकारों और लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए नामांकित किया गया है। नॉर्वे की राजनीतिक पार्टी 'पार्टियेट सेंट्रम' से जुड़े पाकिस्तान वर्ल्ड अलायंस (पीडब्ल्यूए) ने यह घोषणा की है। इससे पर राजनीतिक तौर पर पाकिस्तान की शाहबाज सरकार घिर सकती है, क्योंकि उस पर जबरन इमरान को जेल में बंद रखने के आरोप भी समय-समय पर लगते रहे हैं। यहां बताते चलें कि इससे पहले, 2019 में भी पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का नाम नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था। उस वक्त उन्हें भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने के प्रयासों के लिए यह नामांकन मिला था। दरअसल बालाकोट हवाई हमले के बाद इमरान खान ने दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव को कम करने की पहल की थी, जिसके समर्थन में पाकिस्तान की संसद में एक प्रस्ताव भी पेश किया गया था।

पीडब्ल्यूए ने सोशल मीडिया पर की घोषणा

पार्टियेट सेंट्रम ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स (ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए कहा, कि हमें यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि हमने नामांकन का अधिकार रखने वाले किसी व्यक्ति के साथ मिलकर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया है। इमरान खान को बार-बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए यूं नामित किए जाने से पाकिस्तान की मौजूदा सरकार की खासी किरकिरी होना लाजमी है। इमरान समर्थक इसे ढाल बनाकर शाहबाज सरकार पर निशाना साध सकते हैं। जानकारों की मानें तो इस समय पाकिस्तान की मौजूदा सरकार विश्व में हुए बदलाव से खासे दबाव में है।

रावलपिंडी की जेल में बंद हैं इमरान

इमरान खान 2023 से पाकिस्तान की रावलपिंडी स्थित अडियाला जेल में बंद हैं। जनवरी 2025 में पाकिस्तान की एक कोर्ट ने उन्हें 14 साल की सजा सुनाई। उन पर राष्ट्रीय खजाने को 50 अरब पाकिस्तानी रुपए का नुकसान पहुंचाने का आरोप है। यहां बताते चलें कि 9 मई 2023 को इमरान की गिरफ्तारी के बाद पूरे पाकिस्तान में सेना के अहम ठिकानों पर हमले हुए थे।

क्या इमरान को मिल सकता है नोबेल

नोबेल शांति पुरस्कार के लिए कई चरणों में प्रक्रिया संपन्न होती है। यह तय करना नोबेल समिति के हाथ में होता है कि किसे अंतिम सूची में रखा जाएगा। इमरान खान का नामांकन एक बड़ा मुद्दा बन सकता है, क्योंकि वे इस समय जेल में बंद हैं और पाकिस्तान में राजनीतिक उथल-पुथल जारी है।

बच्चों से दरिंदगी करने वालों को जेल से छूटने से पहले बनाया जाएगा नपुंसक

रोम। वर्ष 2014 में, साइप्रस ने दोषी बाल यौन अपराधियों के लिए अनिवार्य आजीवन कारावास की सजा लागू की थी। प्रस्ताव के अनुसार न्यूनतम सजा को 18 साल तक बढ़ाया जाएगा, और रिहाई की शर्त यह होगी कि उनका एंड्रोजन-ब्लॉकिंग दवाओं के साथ बधियाकरण किया जाएगा। बच्चों से दरिंदगी के दोषी ठहराए गए अपराधियों को जल्द ही जीवन भर जेल में रहने के बजाय रासायनिक ढंग से बधियाकरण करके जेल से बाहर भेजा सकता है। पिछले साल सितंबर में इटली में एक समान योजना पेश की गई थी। इस विवादास्पद योजना का नेतृत्व इटली की दक्षिणपंथी प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने किया था, जो 2022 से सत्ता में हैं। वह कानून और व्यवस्था पर सख्ती से कार्रवाई करना चाहती थीं और नए कानूनों के साथ-साथ कड़े दंड लाने की योजना बना रही थीं। उनकी सरकार के सत्ता में आने के बाद से, उसने दर्जनों नए अपराधों को कायम करने और दंड में बढ़ोतरी करने वाले कानून पेश किए हैं। उनके रासायनिक बधियाकरण की योजनाओं की विपक्षी समूहों द्वारा 'चरमपंथी' और 'मानवता और न्याय का उल्लंघन' कहकर आलोचना की गई है। साइप्रस इस लिस्ट में सबसे नया यूरोपीय देश है, जो बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के दोषियों को रोकने के लिए इस विवादास्पद तरीके का उपयोग करना चाहता है। साइप्रस के डेमोक्रेटिक एलाइनमेंट पार्टी के सांसद मिचालिस यियाकूमी ने देश में बाल शोषण के मामलों में बढ़ोतरी से निपटने के लिए नए कानून की योजना बनाई है।यियाकूमी ने कहा कि संसदीय अध्ययन बताते हैं कि बाल बलात्कारी अक्सर फिर से अपराध करते हैं। यदि आजीवन कारावास नहीं लगाया जाता है, तो आगे के अपराधों और एक और बच्चे के जीवन के विनाश को रोकने के लिए यह अतिरिक्त दंड आवश्यक है। यह अस्वीकार्य है कि वे इतनी छोटी सजा काटें और बिना कड़े प्रतिबंधों के रिहा हो जाएं। यह विधेयक अभी साइप्रस में मंजूर नहीं हुआ है और इसे बाद में संसद में चर्चा के लिए पेश किया जाएगा, जबकि इसके विरोधी इसे मानवाधिकारों का उल्लंघन मानते हैं। यह प्रक्रिया पहले से ही 12 यूरोपीय देशों में स्वैच्छिक रूप से उपयोग की जा रही है। रूस और पोलैंड में और कुछ अमेरिकी राज्यों में कुछ अपराधों के लिए अनिवार्य रासायनिक बधियाकरण की अनुमति है। 2024 में कजाकिस्तान ने बड़े पैमाने पर रासायनिक बधियाकरण की घोषणा की। ग्यारह बाल यौन अपराधियों को देश के यौन अपराधियों पर नवीनतम कार्रवाई में एक साल में 24 इंजेक्शन लगवाए गए। उसी साल की शुरुआत में मेडागास्कर की संसद ने एक नया कानून मंजूर किया, जिसके तहत 10 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ बलात्कार करने का दोषी पाए जाने पर सर्जिकल बधियाकरण और आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। जबकि यदि पीड़ित की उम्र 10 से 13 साल के बीच है, तो उन्हें रासायनिक बधियाकरण और 15 से 20 साल के कठोर श्रम की सजा दी जाएगी।

तीसरे विश्व युद्ध की आहटः नागरिकों की सुरक्षा के लिए स्वीडन ने बनाए परमाणु निरोधक बंकर

स्टॉकहोम

रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बीच स्वीडन को लगने लगा है कि तीसरा विश्व युद्ध होगा। इसी आशंका के बीच स्वीडन ने आपनी तैयारी शुरु कर दी है। नागरिकों को सुरक्षित करने के लिए 64 हजार से अधिक सुरक्षा बंकर और आश्रय स्थल बनाए हैं। इससे नागरिकों को शारीरिक, रासायनिक, जैविक, और परमाणु हमलों के नुकसान से बचाया जा सकता है। स्वीडन की नागरिक सुरक्षा एजेंसी (एमएसबी) ने घोषणा की है कि वह अपनी नागरिक सुरक्षा बंकरों के नवीनीकरण के लिए 100 मिलियन क्रोनर का निवेश करेगी। इस कदम का उद्देश्य नागरिकों को शारीरिक, रासायनिक, जैविक, और परमाणु हमलों से बचाना है।

स्वीडन में पहले से ही लगभग 64,000 सुरक्षा बंकर और आश्रय स्थल हैं, जो दुनिया के किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक हैं। ये बंकर लगभग सात मिलियन नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम हैं, जो स्वीडन की कुल जनसंख्या का दो-तिहाई हिस्सा है। इसके बावजूद, स्वीडन ने अपने सुरक्षा उपायों को और अधिक उन्नत करने के लिए बंकरों की जांच और नवीनीकरण प्रक्रिया को तेज कर दिया है। विशेष रूप से, मार्च 2024 में स्वीडन के नाटो में शामिल होने के बाद से इन बंकरों की सुरक्षा पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। स्वीडन के नागरिक सुरक्षा मंत्री ने बताया कि इस नवीनीकरण परियोजना के तहत, बंकरों में मौजूद फिल्टर सिस्टम को उन्नत किया जाएगा ताकि रासायनिक और रेडियोलॉजिकल हमलों से नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इसके अतिरिक्त, इन बंकरों को परमाणु हमलों, बम के टुकड़ों, शॉकवेव्स, और हीटवेव से बचाव के लिए भी डिजाइन किया गया है। बंकरों में नागरिकों को रेडियोधर्मी फॉलआउट, रासायनिक गैस, और जैविक हथियारों से सुरक्षा प्राप्त होगी।

स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने जनवरी 2024 में कहा था, स्वीडन युद्ध में नहीं है, लेकिन शांति भी नहीं है। यह बयान यूरोप में बढ़ते सुरक्षा खतरे और एक संभावित बड़े संघर्ष की आशंका को दर्शाता है। स्वीडन में इस प्रकार की तैयारियां विशेष रूप से इसलिए की जा रही हैं क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के परिणामस्वरूप सुरक्षा स्थिति अस्थिर हो गई है।

ज्वालामुखी से निकला लावा

आईसलैंड में एक ज्वालामुखी से निकलता हुआ लावा।

अमेरिका से डिपोर्ट किए गए 10 भूटानी शरणार्थियों में से तीन को नेपाल पुलिस ने गिरफ्तार किया

काठमांडू

अमेरिका द्वारा डिपोर्ट किए गए 10 भूटानी नागरिकों को भूटान सरकार ने अपने यहां रखने से इनकार करते हुए उन सभी को वापस नेपाल भेज दिया है। इनमें से तीन भूटानी शरणार्थियों को नेपाल में अवैध रूप से प्रवेश करने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया है। अमेरिका जाने से पहले ये सभी 10 लोग नेपाल के भूटानी शरणार्थी शिविरों में रह रहे थे।

नेपाल के झापा जिले के एसपी मिलन केसी ने बुधवार को मीडियाकर्मियों को बताया कि अमेरिका से डिपोर्ट किए जाने के बाद अवैध रूप से नेपाल में प्रवेश करने वाले 10 में से तीन भूटानी नागरिकों को मंगलवार शाम को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में पता लगा है कि अमेरिका से डिपोर्ट होने के बाद भूटान सरकार ने उन्हें अपने यहां रखने से इनकार कर दिया जिसके बाद वो भारत के रास्ते नेपाल में दोबारा आ गए हैं।

अमेरिका की पूर्ववर्ती सरकार द्वारा नेपाल में रह रहे भूटानी शरणार्थियों को ले जाया गया था लेकिन अब उनको अमेरिका से वापस भेजा जा रहा है। बीते सोमवार को अमेरिका से दिल्ली होते हुए थिंपू भेजे गए 10 नागरिकों को भूटान सरकार ने अपने यहां रखने से इनकार किया है। नेपाल में पुलिस नियंत्रण में लिए गए भूटानी नागरिकों ने बताया कि अमेरिका से डिपोर्ट होने के बाद उन्हें जब सोमवार को थिंपू एयरपोर्ट पर उतारा गया तो वहां की सरकार ने प्रति व्यक्ति 30 हजार रुपये देकर भूटान से विदा कर दिया। नेपाल में गिरफ्तार किए गए भूटानी नागरिकों ने बताया कि चूंकि वो नेपाल के भूटानी शरणार्थी शिविर से अमेरिका गए थे इसलिए भूटान सरकार ने उन्हें दोबारा शरणार्थी शिविर में रहने के लिए भेजा है।

डेमोक्रेटिक बुकर 25 घंटे तक सीनेट में लगातार बोलते रहे राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों के खिलाफ

वाशिंगटन

अमेरिकी सांसद (सीनेटर) कॉरी बुकर ने मंगलवार को सीनेट के इतिहास में सबसे लंबा भाषण देकर नया रिकॉर्ड स्थापित किया। न्यूजर्सी से डेमोक्रेटिक सीनेटर बुकर ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के खिलाफ विरोध जताते हुए 25 घंटे और पांच मिनट लगातार बोलकर1957 में सीनेटर स्ट्रॉम थरमंड के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया। थरमंड ने सिविल राइट्स एक्ट के खिलाफ 24 घंटे 18 मिनट तक भाषण दिया था।

खबर में बुकर के इस ऐतिहासिक भाषण पर विस्तार से चर्चा की गई है। 55 वर्षीय बुकर ने सोमवार शाम सात बजे (स्थानीय समय) सीनेट के मंच पर अपनी बात शुरू की और मंगलवार रात 8:05 बजे तक लगातार बोलते रहे। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य संयुक्त राज्य सीनेट के सामान्य कामकाज को तब तक बाधित करना है, जब तक मैं शारीरिक रूप से सक्षम हूं। अपने भाषण की शुरुआत में उन्होंने जोर देकर कहा, मैं रात इसलिए खड़ा हूं क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा देश

संकट में है। बुकर का यह भाषण तकनीकी रूप से फिलिबस्टर नहीं था। इसका सीधा मतलब है कि यह किसी खास विधेयक को रोकने के लिए नहीं था। न ही कार्यवाही को रोकने के लिए किसी विशिष्ट उपाय पर बहस के दौरान हुआ। यह ट्रंप प्रशासन की नीतियों के खिलाफ था। बुकर ने भाषण में ट्रंप प्रशासन पर अमेरिकियों की सुरक्षा, वित्तीय स्थिरता और लोकतंत्र की मूलभूत नींव को क्षति पहुंचाने का आरोप लगाया। कॉरी ने कहा कि पिछले 71 दिन में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकियों को हद से ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। बुकर ने मेडिकेड और सोशल सिक्योरिटी में कटौती की आशंका, शिक्षा विभाग पर हमला और ट्रंप की विदेश नीति का तीखा विरोध किया। उन्होंने अपने मतदाताओं के पत्र भी पढ़े। इनमें ट्रंप की नीतियों से होने वाली परेशानियों का जिक्र था। बुकर ने सिविल राइट्स आंदोलन के प्रतीक जॉन लुईस का कई बार उल्लेख किया। इस दौरान कई डेमोक्रेटिक सीनेटरों ने बुकर का समर्थन किया। इनमें चक शूमर प्रमुख हैं। शूमर ने रिकॉर्ड टूटने के बाद कहा, क्या आपको पता है कि आपने अभी रिकॉर्ड तोड़ा है क्या आपको पता है कि यह समूह आप पर कितना गर्व करता है।

नहीं थम रहे भूकंप के झटके, म्यांमार और थाईलैंड के बाद हिली पाकिस्तान की धरती

इस्लामाबाद। दुनिया में लगभग हर रोज कहीं न कहीं भूकंप के कम या ज्यादा झटके महसूस हो रहे हैं। म्यांमार और थाईलैंड में तबाही मचाने के बाद भूकंप ने अब पाकिस्तान में खबलची मचाई है। पाकिस्तान में देर रात भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। इस भूकंप की वजह से पाकिस्तान की धरती कांप उठी। रात में सोए लोगों की नींद खुल गई और वे घर से बाहर भागने लगे। फिलहाल, किसी नुकसान की कोई खबर नहीं है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक, पाकिस्तान में 2 अप्रैल को तड़के 2 बजकर 58 मिनट पर यह भूकंप आया। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.3 थी। इसकी वजह से पाकिस्तान की धरती रात में ही डोलने लगी। लोगों को बेड हिलते महसूस हुए। फिलहाल, अब तक किसी के नुकसान की कोई खबर नहीं है। यह भूकंप ऐसे वक्त में आया है, जब म्यांमार और बैंकॉक में भूकंप की विनाशलीला दुनिया देख रही है। म्यांमार में पिछले सप्ताह आए 7.7 तीव्रता के विनाशकारी भूकंप में मरने वालों की संख्या 2,700 से अधिक हो गई है जबकि हजारों लोग घायल हैं।